



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]
No. 667]नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2003/श्रावण 3, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2003/SRAVANA 3, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2003

आय-कर

का.आ. 856(अ)— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम आय की विवरणी का इलेक्ट्रोनिक प्रस्तुतिकरण स्कीम, 2003 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- (3) यह ऐसे व्यष्टि को लागू होती है जिसकी “वेतन” शीर्ष के अधीन आय है और जिसकी “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कोई आय नहीं है, जिसका अहमदाबाद बैंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में कर के लिए निर्धारण किया गया है या निर्धारणीय है।

2. परिभाषाएँ-- इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्नथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;
- (ख) “बोर्ड” से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (ग) “पात्र व्यक्ति” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी “वेतन” शीर्ष के अधीन आय है और जिसकी “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कोई आय नहीं है जिसको स्थायी लेखा संख्या आबंटित की गई है और जिसका पैरा (1) के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट स्थानों में से किसी स्थान में जहां स्कीम लागू है, कर के लिए निर्धारण किया गया है या निर्धारणीय है ;
- (घ) “ई-विवरणी” से आय की सम्यक् रूप से सत्यापित् विवरणी पत्र द्वारा समर्थित इस स्कीम के अधीन दी गई आय की विवरणी के इलेक्ट्रोनिक रूप से पारेषित आंकड़े अभिप्रेत हैं ;
- (ङ) “ई-विवरणी प्रशासक” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो इस स्कीम के प्रशासन के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अभिहित आय-कर आयुक्त की रैंक से नीचे का नहीं है ;
- (च) “ई-विवरणी मध्यवर्ती” से ऐसा व्यक्ति जो एक कंपनी है, अभिप्रेत है जिसे स्कीम के अधीन ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में प्राधिकृत किया गया है ;
- (छ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. ई-विवरणी का फाइल किया जाना--(1) कोई पात्र व्यक्ति अपने विकल्प पर किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए, आय की विवरणी, नियंत तारीख को या उसके पूर्व एक अतिरिक्त पद्धति के रूप में दे सकेगा।
- (2) कोई पात्र व्यक्ति अपनी आय की वह विवरणी जिसकी उससे अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए देने की अपेक्षा की जाती है, किसी ऐसे ई-विवरणी मध्यवर्ती को दे सकेगा जो ऐसी विवरणी के आंकड़ों का

अंकीकरण करेगा और ई-विवरणी प्रशासक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित सर्वर को नियत तारीख को या उससे पूर्व इलेक्ट्रोनिक रूप से पारेषित करेगा।

(3) ई-विवरणी मध्यवर्ती, किसी पात्र व्यक्ति से प्राप्त आय के विवरणी पत्र को ई-विवरणी प्रशासक द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रोनिक आंकड़ों के लिए अनंतिम रसीद के जारी किए जाने के पंद्रह दिन से अपश्चात् निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

4. आय की पुनरीक्षित विवरणी —यदि पात्र व्यक्ति ने रकीम के अधीन आय की विवरणी दी है तो वह अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) के अधीन आय की पुनरीक्षित विवरणी दे सकेगा।

5. ई-विवरणी मध्यवर्ती का प्राधिकार-- (1) ई-विवरणी प्रशासक एक या अधिक ऐसी कंपनियों को जिनकी पर्याप्त वित्तीय क्षमता, वास्तविक और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना है और जिन्हें, वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में साबित अनुभव है इस निमित्त समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु यह कि कोई कंपनी जिसने आय-कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जिसका आपराधिक अभिलेख है ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में प्राधिकृत नहीं की जाएगी।

(2) ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में प्राधिकृत किए जाने के लिए इच्छुक कंपनी ई-विवरणी प्रशासक को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी।

(3) ई-विवरणी प्रशासक किसी कंपनी को ई-विवरणी मध्यवर्ती प्राधिकृत किए जाने के पूर्व उसकी तकनीकी उपयुक्तता का, जिसके अंतर्गत आंकड़ों के पारेषण के लिए सफल जांच भी है, मूल्यांकन करेगा।

(4) उप पैरा (1) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए किसी कंपनी को ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा।

(5) ई-विवरणी प्रशासक प्रत्येक ई-विवरणी मध्यवर्ती के लिए ई-विवरणी मध्यवर्ती पहचान संख्या (ईआरआईआईएन) के नाम से ज्ञात एक पहचान संख्या और एक संकेत शब्द (पासवर्ड) जारी करेगा जो एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए विधिमान्य होगा ।

(6) बोर्ड, अनुचित आचरण, दुर्व्यपदेशन, अनैतिक व्यवहार, कपट या पात्र व्यक्ति की स्थापित कमी के आधारों पर या ऐसे अन्य आधार पर जो वह ठीक समझे, किसी ई-विवरणी मध्यवर्ती के प्राधिकार को प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

6. पात्र व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ—इस स्कीम के अधीन आय की अपनी विवरणी देने का विकल्प लेने वाला पात्र व्यक्ति—

(1) यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी आय की विवरणी इस स्कीम के अंतर्गत आती है ;
 (2) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अपनी ई-विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए अपने अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए ई-विवरणी मध्यवर्तियों में से किसी के लिए सहमति देगा।

7. ई-विवरणी मध्यवर्ती द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ— (1) ई-विवरणी मध्यवर्ती यथास्थिति पात्र व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित आय का विवरणी पत्र प्राप्त करेगा या पात्र व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आय की विवरणी तैयार करेगा ।

(2) ई-विवरणी मध्यवर्ती तब सत्यापन के लिए ई-विवरणी प्रशासक को, पात्र व्यक्ति द्वारा दी गई रथायी लेखा संख्या ऑन लाइन प्रस्तुत करेगा ।

(3) सत्यापन के सम्पन्न न होने की दशा में, ई-विवरणी मध्यवर्ती ऑनलाइन सत्यापन के लिए रथायी लेखा संख्या अभिलेख की पुनः जांच करेगा और उसे पुनः प्रस्तुत करेगा । यदि सत्यापन फिर भी सम्पन्न नहीं हो पाता है तो वह नियत तारीख को या उसके पूर्व संबद्ध निर्धारण अधिकारी के समक्ष विवरणी पत्र फाइल करेगा और पात्र व्यक्ति को अभिस्थीकृति सौंप देगा ।

(4) यदि सत्यापन सम्पन्न हो जाता है तो ई-विवरणी मध्यवर्ती आय की विवरणी के आंकड़ों का अंकीकरण करेगा और अपनी ई-विवरणी मध्यवर्ती पहचान संख्या (ईआरआईआईएन) का उपयोग करते हुए ई-विवरणी प्रशासक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फार्मेट और ई-विवरणी प्रशासक द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुरूप उसे सर्वर को पारेषित करेगा।

(5) ई-विवरणी प्रशासक पारेषित आंकड़ों की अभिस्वीकृति की पुष्टि में ई-विवरणी मध्यवर्ती को ऑन-लाइन एक अनंतिम रसीद जारी करेगा।

(6) इस प्रक्रम पर आंकड़ों के असफल पारेषण की दशा में, ई-विवरणी मध्यवर्ती, ई-विवरणी प्रशासक द्वारा संसूचित त्रुटि कोड का विश्लेषण करेगा, त्रुटि कोड और उसके पास उपलब्ध विवरणी पत्र के आधार पर आंकड़ों को सही करेगा और उसे ई-विवरणी प्रशासक को पुनः प्रस्तुत करेगा।

(7) ई-विवरणी मध्यवर्ती आय की विवरणी के आंकड़ों के सफल पारेषण पर ऑन-लाइन उसके द्वारा प्राप्त अनंतिम रसीद की दो प्रतियां मुद्रित करेगा। वह उसकी एक प्रति अभिस्वीकृति शीट पर और दूसरी प्रति को आय की विवरणी पत्र के पहले पृष्ठ पर चिपकाएगा।

(8) ई-विवरणी मध्यवर्ती, आय के विवरणी पत्र को उसके संलग्नकों और अनंतिम रसीद के प्रिंट आउट के साथ अनंतिम रसीद के जारी किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसके लिए अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेगा।

(9) ई-विवरणी मध्यवर्ती, पात्र व्यक्ति को आय की विवरणी की अभिस्वीकृति परिदृत करेगा और निर्धारण अधिकारी को आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से सात दिन के भीतर विवरणी पत्र प्रस्तुत किए जाने के संकेत के रूप में ई-विवरणी प्रशासक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फार्मेट में संरचना को विवरणी की अभिस्वीकृति संख्या भी पारेषित करेगा।

(10) अनंतिम रसीद के जारी करने की तारीख आय की विवरणी फाइल करने की तारीख समझी जाएगी, यदि विवरणी पत्र अनंतिम रसीद के जारी करने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी के पास फाइल कर दी गई है।

(11) किसी कारण से आंकड़ों के असफल पारेषण की दशा में, ई-विवरणी मध्यवर्ती, त्रुटि रिपोर्ट के जारी करने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संबद्ध निर्धारण अधिकारी को आय की विवरणी पत्र को उसके संलग्नकों और त्रुटि रिपोर्ट के प्रिंट आउट के साथ भेजेगा। ऐसे मामले में ई-विवरणी प्रशासक द्वारा त्रुटि रिपोर्ट के जारी करने की तारीख आय की विवरणी के फाइल करने की तारीख समझी जाएगी।

8. ई-विवरणी पर कार्रवाई-(1) ई-विवरणी पर पूर्विकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

(2) निर्धारिती को शोध्य प्रतिदाय, यदि कोई हो, उसके विकल्प पर या तो भारतीय रिजर्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन स्कीम (ईसीएस) का उपयोग करते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा या निर्धारिती को सीधे भेज दिया जाएगा।

9. ई-विवरणी मध्यवर्ती के साधारण उत्तरदायित्व-(1) ई-विवरणियों का समय के भीतर फाइल किया जाना--ई-विवरणी मध्यवर्ती, यह सुनिश्चित करेगा कि विवरणी का इलेक्ट्रॉनिक भाग अधिनियम की धारा 139 में यथा उपबंधित आय की विवरणियों के फाइल करने की नियत तारीख को या उसके पूर्व पारेषित कर दिया जाता है, यदि आय की विवरणी नियत तारीख को या उसके पूर्व पात्र व्यक्ति द्वारा उसके इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल करने के लिए भेज दी गई है।

(2) शुद्धता--ई-विवरणी मध्यवर्ती, आय की विवरणी से आंकड़ों का प्रतिलेखन करते समय और उसके पारेषण के दौरान आंकड़ों की प्रविष्टि की शुद्धता सुनिश्चित करेगा।

(3) आंकड़ों का भंडारण— ई-विवरणी मध्यवर्ती, आय की विवरणी के इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े ऐसे फार्मेट में जो ई-विवरणी प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के लिए रखेगा ।

(4) अभिस्थीकृति फाइल का भंडारण— ई-विवरणी मध्यवर्ती, उसके माध्यम से फाइल की गई विवरणियों के संबंध में जारी की गई अनंतिम रसीदों से संबंधित सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के लिए रखेगा ।

(5) पात्र व्यक्ति को सूचना— ई-विवरणी मध्यवर्ती, उसके द्वारा भेजी गई ई-विवरणी पत्र की प्रति पात्र व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा ।

(6) कर सूचना की गोपनीयता— ई-विवरणी मध्यवर्ती उस सूचना की गोपनीयता पात्र व्यक्ति, निर्धारण अधिकारी या ई-विवरणी प्रशासक की अनुज्ञा के सिवाय सुनिश्चित करेगा जो स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान उसके कब्जे में आती है ।

(7) ई-विवरणी मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी कर्मचारी, अभिकर्ता, विशेष अधिकारी आदि इस स्कीम के उपबंधों तथा ई-विवरणी प्रशासक द्वारा जारी किए गए सभी निदेशों का पालन करते हैं ।

(8) सूचना में परिवर्तनों की तत्पर अधिसूचना— ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में प्राधिकार के लिए उसके द्वारा फाइल किए गए आवेदन में अंतर्विष्ट सूचना में किसी परिवर्तन की ई-विवरणी प्रशासक को तत्परता से सूचना देगा ।

10. ई-विवरणी प्रशासक की शक्तियां— पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ई-विवरणी प्रशासक—

(1) स्कीम के दिन-प्रतिदिन प्रशासन के लिए आंकड़े के सुरक्षित प्रग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, फार्मेट और मानक विनिर्दिष्ट करेगा ।

(2) स्कीम की तकनीकी अपेक्षाएँ जिनके अंतर्गत ई-विवरणी मध्यवर्तियों के कार्य का पुनर्विलोकन करने, शिकायतों का सत्यापन उनके द्वारा जारी की गई विज्ञापन सामग्री की समीक्षा भी है और ऐसे अन्य मामलों का जो वह ठीक समझे, ई-विवरणी मध्यवर्ती द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

[अधिसूचना सं. 181/2003/फा. सं. 142/12/2003-टीपीएल]

पूजा जिंदल, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(Central Board of Direct Taxes)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2003

INCOME-TAX

S.O. 856(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1B) of section 139 of Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following scheme, namely: –

1. **Short title, commencement and application.**— (1) This scheme may be called the Electronic Furnishing of Returns of Income Scheme, 2003.
 (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
 (3) It applies to an individual having income under the head "Salaries" and not having any income under the head "Profits and gains of business or profession", who is assessed or assessable to tax at Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata and Mumbai.
2. **Definitions.**— In this scheme, unless the context otherwise requires,— (a) "Act" means the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
 (b) "Board" means the Central Board of Direct Taxes constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963);
 (c) "eligible person" means a person having income under the head "Salaries" and not having any income under the head "Profits and gains of business or profession", who has been allotted a permanent account number, and who is assessed or assessable to tax at any of the places specified in sub-para (3) of paragraph 1 to which the scheme is applicable;
 (d) "e-Return" means electronically transmitted data of return of income furnished under this scheme, supported by a duly verified paper return of income;
 (e) "e-Return Administrator" means an officer not below the rank of Commissioner of Income-tax designated by the Board for the purpose of the administration of this scheme;
 (f) "e-Return Intermediary" means a person, being a company, authorised to be an e-Return Intermediary under this scheme;
 (g) All other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Filing of e-Returns.- (1) An eligible person may, at his option, as an additional mode, furnish a return of income for any previous year on or before the due date.

(2) An eligible person may furnish his return of income which he is required to furnish under sub-section (1) of section 139 of the Act for the assessment year 2003-2004 and subsequent assessment years, to an e-Return Intermediary who shall digitise the data of such return and transmit the same electronically to a server designated for this purpose by the e-Return Administrator, on or before the due date.

(3) The e-Return Intermediary shall submit the paper return of income received from an eligible person to the Assessing Officer not later than fifteen days from the issue of the provisional receipt for the electronic data received by the e-Return Administrator.

4. Revised return of income.- An eligible person may furnish a revised return of income under sub-section (5) of section 139 of the Act if he has furnished a return of income under the scheme.

5. Authorisation of e-Return Intermediary.- (1) The e-Return Administrator may authorise one or more companies, having adequate financial capacity, physical and Information Technology infrastructure, proven experience in the field of providing financial services, to be an e-Return Intermediary as per the guidelines issued by the Board from time to time in this behalf:

Provided that no company which has defaulted in payment of income tax or having a criminal record shall be authorised to be an e-Return Intermediary.

(2) A Company desirous to be authorised as an e-Return Intermediary may submit an application to the e-Return Administrator.

(3) The e-Return Administrator shall evaluate the technical suitability of a company including successful check for data transmission before authorising it to be an e-Return Intermediary.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-para (1) and (3), the Board may authorise a company to be an e-Return Intermediary for the financial year 2003-04.

(5) The e-Return Administrator shall issue an identification Number to be called e-Return Intermediary Identification Number (ERIIN) and a password to each e-Return Intermediary, which shall be valid for a particular financial year.

(6) The Board may revoke the authorisation of an e-Return Intermediary, on grounds of improper conduct, misrepresentation, unethical practices, fraud or established lack of service to the eligible persons, or on such other ground as it may deem fit.

6. Procedure to be followed by eligible persons.- An eligible person opting to furnish his return of income under this scheme shall –

- (1) ensure that his return of income falls under this scheme;
- (2) give consent to any one of the e-Return Intermediaries to act as his agent for the purpose of furnishing his e-Return for the relevant assessment year.

7. Procedure to be followed by e-Return Intermediary.- (1) An e-Return Intermediary shall receive a paper return of income duly verified by the eligible person, or shall prepare the return of income on the basis of the documents furnished by the eligible person, as the case may be.

(2) An e-Return Intermediary shall then submit online the permanent account number given by the eligible person, to e-Return Administrator for verification.

(3) In case the verification does not succeed, the e-Return Intermediary shall recheck and resubmit the permanent account number record for online verification. If the verification still does not succeed, he shall file the paper return before the concerned Assessing Officer on or before the due date, and hand over the acknowledgement to the eligible person.

(4) If the verification succeeds, the e-Return Intermediary shall digitise the data of the return of income and transmit the same to the server in such format as specified by the e-Return Administrator using its e-Return Intermediary Identification Number (ERIIN), and in conformity with the instructions given by the e-Return Administrator.

(5) The e-Return Administrator shall issue a provisional receipt online to the e-Return Intermediary in confirmation of the acceptance of the data transmitted.

(6) In case of any unsuccessful transmission of data at this stage, the e-Return Intermediary shall analyse the error code communicated by the e-Return Administrator, correct the data on the basis of the error code and the paper return available with him and resubmit the same to the e-Return Administrator.

(7) The e-Return Intermediary shall print two copies of the provisional receipt received by him online on successful transmission of the data of the return of income. It shall affix one copy of the same on the acknowledgement sheet and the other on the first page of the paper return of income.

(8) The e-Return Intermediary shall furnish to the Assessing Officer the paper return of income along with its enclosures and the print out of the provisional receipt within fifteen days from the date of issue of the provisional receipt and shall obtain an acknowledgement for the same.

(9) The e-Return Intermediary shall deliver the acknowledgement of the return of income to the eligible person, and also transmit the acknowledgement number of the return to the server in such format as specified by the e-Return Administrator in token of having furnished the paper return, within seven days from the date of furnishing the return of income to the Assessing Officer.

(10) The date of issue of the provisional receipt shall be deemed to be the date of filing of return of income if the paper return has been filed with the Assessing Officer within fifteen days from the date of the issue of the provisional receipt.

(11) In case of an unsuccessful transmission of data for any reason, the e-Return Intermediary shall furnish the paper return of income along with its enclosures and the print out of the error report to the concerned Assessing Officer within fifteen days from the date of issue of the error report. In such a case, the date of issue of the error report by the e-Return Administrator shall be deemed to be the date of filing of the return of income.

8. Processing of e-Return.-

(1) The e-Return shall be processed, on priority basis.

(2) The refund, if any, due to the assessee shall, at his option, be either credited by the Assessing Officer directly to his bank account, using the Electronic Clearance Scheme (ECS) of the Reserve Bank of India, or be directly sent to the assessee.

9. General responsibilities of e-Return Intermediary.-

(1) **Timely filing of e-Returns.-** The e-Return Intermediary shall ensure that the electronic portion of the return is transmitted on or before the due date of filing of returns of income as provided in section 139 of the Act, if the return of income has been submitted for its electronic filing by the eligible person on or before the due date.

(2) **Accuracy.-** The e-Return Intermediary shall ensure accuracy of the data entry while transcribing the data from the return of income and during its transmission.

(3) **Storage of data.-** The e-Return Intermediary shall retain for a period of one year from the end of the relevant assessment year, the electronic data of the return of income in such format as specified by the e-Return Administrator.

(4) **Storage of acknowledgement file.—**The e-Return Intermediary shall retain for a period of one year from the end of the relevant assessment year the information relating to provisional receipts issued in respect of the returns filed through it.

(5) **Information to eligible persons.—**The e-return Intermediary shall provide the eligible person paper copy of the e-Return submitted by it.

(6) **Confidentiality of tax information** – The e-Return Intermediary shall ensure confidentiality of information that comes to his possession during the course of implementation of this scheme, save with the permission of the eligible person, Assessing Officer or e-Return Administrator.

(7) The e-Return Intermediary shall ensure that all his employees, agents, franchisees, etc., adhere to the provisions of this scheme as well as all directions issued by e-Return Administrator.

(8) **Prompt notification of changes in information:** The e-Return Intermediary shall promptly inform the e-Return Administrator any change in the information contained in the application filed by it for authorisation as e-Return Intermediary.

10. Powers of e-Return Administrator: Without affecting the generality of the foregoing provisions, the e-Return Administrator shall—

- (1) specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data, for the day to day administration of the Scheme;
- (2) ensure compliance by e-Return Intermediaries with the technical requirements of the scheme, including review of the functioning of e-Returns Intermediaries, verification of any complaints, scrutinising advertising material issued by them, and such other matters as he deems fit.

[Notification No. 181/2003/F. No. 142/12/2003-TPL]

PUJA JINDAL, Under Secy.